दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

***सुरक्षित* : 15 मार्च, 2024**

***उद्घोषित* : 6 मई, 2024**

<u>सि.मू. (वाणि.बौ.सं.अनु.-सि.पु.) 695/2022</u>

इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मनीष कुमार मिश्रा, सुश्री आकांक्षा सिंह, सुश्री सलोनी कासलीवाल और सुश्री तरुशी अग्रवाल, अधिवक्तागण

बनाम

मैसर्स 4पिनफोटेक और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री निधि रमन, कें.सर.स्था.अधि. के साथ श्री जुबिन सिंह, श्री आकाश मिश्रा, श्री देब चरंदे, अधिवक्तागण और श्री हेमंत खोसला, भारत संघ/प्र.-2 के लिए कॉपीराइट के उप रजिस्ट्रार।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनीश दयाल.</u>

1. यह याचिका कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (“**कॉपीराइट अधिनियम**”) की धारा 50 के तहत दायर की गई है, जिसमें कॉपीराइट में सुधार और प्रत्यर्थी सं.1 ("**आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण**") के पक्ष में दिनांक 12 दिसंबर, 2018 को "**वर्चुअल एक्सपो**" नामक साहित्यिक कृति के लिए सं. एल-79443/2018 द्वारा दिए गए रजिस्ट्रीकरण को हटाने की मांग की गई है।

2. प्रत्यर्थी सं.1 14 जुलाई, 2022 को कार्यवाही शुरू होने और उसके बाद न्यायालय द्वारा निर्धारित एक दर्जन से अधिक तारीखों के बाद से मामले में पेश नहीं हुआ है। इसलिए, 05 जुलाई, 2023 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं.1 पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. याचिकाकर्ता और कॉपीराइट के रजिस्ट्रार ("**प्रत्यर्थी सं. 2**) की ओर से प्रस्तुतियाँ दी गईं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4. इस मुद्दे में **"वर्चुअल एक्सपो"** शीर्षक वाले निम्नलिखित दस्तावेज़ में आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण शामिल है, जिसे यहाँ उद्धृत किया गया है:

वर्चुअल एक्सपो

> **इस वर्चुअल शो का उद्देश्य कुशल तरीके से लक्षित दर्शकों के लिए हरित अनुरक्षनीय समाधान प्रस्तुत करना है।**

वर्चुअल शो विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पर्यटन, रोजगार मेला, भवन निर्माण सामग्री, संपत्ति आदि का आयोजन करता है।

प्रतिभागियों को उपलब्ध व्यवसाय में धन की बचत, यात्रा समय, दुकान की निर्माण लागत, रसद समस्या को दूर करना, यातायात में कमी, कागज की बचत तथा कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करना भी शामिल है।

ई-ब्रोचर द्वारा कागज की बचत करना है।

ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने सुविधाजनक स्थान घर, कार्यालय कहीं से भी एक्सपो में भाग लेता है।

वर्चुअल एक्सपो भाग लेने वाले प्रदर्शकों के लिए बजट के अनुकूल है और उपस्थित लोगों के लिए निःशुल्क है।

उत्पाद नियमावली, डेमो, ब्रोचर, पोस्टर, वीडियो और अन्य सूचनात्मक सामग्री आगंतुकों द्वारा आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

वर्चुअल एक्सपो पूरे भारत में संभावित ग्राहकों को जोड़ने का एक किफायती और सुविधाजनक तरीका है।

5. याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में परिचालन करने वाली कंपनियों के एक बहुराष्ट्रीय समूह का एक अभिन्न अंग है। यह देश की अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक होने का दावा करता है और सम्मेलनों और संगोष्ठियों के आयोजन सहित कई कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है।

6. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 2006 से हर साल देश भर में कई बड़े-बड़े कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार, प्रदर्शनी और प्रदर्शन विनिर्माण, खाद्य, आतिथ्य, आभूषण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और रसद आदि सहित विभिन्न उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य को सक्षम और सशक्त बनाते हैं।

7. वर्ष 2020 में, याचिकाकर्ता को अपने सहयोगी बोलोग्ना फियर के सहयोग से *"कॉस्मोप्रॉफ इंडिया"* नामक एक कार्यक्रम आयोजित करना था। हालांकि, कोविड-19 महामारी और उसके बाद हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, याचिकाकर्ता का व्यवसाय ठप हो गया और इसलिए याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी।

8. नतीजतन, *"कॉस्मोप्रॉफ"* को एक आभासी प्रदर्शनी कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया गया और *"वर्चुअल एक्सपो"* शब्दों का उपयोग घटना के शाब्दिक और सामान्य विवरण के रूप में किया गया। यह कार्यक्रम 05 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुसार यह एक बड़ी सफलता थी।

9. इसके बाद, इस कार्यक्रम को *"वर्चुअल एक्सपो"* के रूप में वर्णित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम कैटलॉग, सोशल मीडिया पोस्ट और सोशल मीडिया हैशटैग प्रचारित किया गया।

10. 25 अक्टूबर, 2020 को याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी सं.1 से कानूनी नोटिस मिला, जिसमें आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण का मालिक होने का दावा किया गया था।

11. प्रत्यर्थी सं.1 आभासी माध्यमों से *"वर्चुअल एक्सपो"* शब्द का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकारों का दावा कर रहा था। प्रत्यर्थी सं.1 द्‌वारा 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) का हर्जाना भी मांगा गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता कॉपीराइट अधिनियम की धारा 50 के तहत पीड़ित व्यक्ति होने का दावा करता है।

12. जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर में बरकरार रखा जा सकता है और क्या वह प्रथमतः कॉपीराइट योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता कॉपीराइट अधिनियम की धारा 50 के तहत एक "*व्यथित व्यक्ति*" है जिसे प्रत्यर्थी सं. 1 द्‌वारा कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसने "वर्चुअल एक्सपो" शब्द का उपयोग करने के साथ-साथ किसी भी आभासी प्रदर्शनी के संचालन को रोकने और हर्जाने की मांग की है। स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता की कॉपीराइट रजिस्टर में सुधार और आक्षेपित रजिस्ट्रीकरण को हटाने की मांग में वास्तविक और ठोस रुचि है।

13. आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि यह कॉपीराइट अधिनियम की धरा 2(1)(ण) के तहत

परिभाषित *"साहित्यिक कृति"* है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13 के तहत ऐसे कार्य पर कॉपीराइट लागू होता है और अधिनियम की धारा 17 निर्दिष्ट करती है कि कृति का लेखक कॉपीराइट का पहला मालिक होगा।

14. जो रजिस्ट्रीकृत किया गया है वह स्पष्ट रूप से केवल एक दस्तावेज है जो आभासी प्रदर्शनी की अवधारणा का वर्णन करने का प्रयास करता है। अनिवार्य रूप से, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ में कहा गया है कि एक आभासी एक्सपो के कुछ ठोस लाभ हैं, अन्य बातों के *साथ-साथ*, कि यह एक दीर्घकालिक समाधान है, कुशल है, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जा सकता है, पैसे की बचत करता है, यात्रा का समय, निर्माण लागत, रसद, कागज बचाता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, पहुंच सुनिश्चित करता है, बजट के अनुकूल है, मैनुअल, ब्रोचर, वीडियो डाउनलोड करने की अनुमति देता है, और ग्राहकों और मुवक्किलों को जोड़ने का एक किफायती और सुविधाजनक तरीका है।

15. यह स्पष्ट रूप से, किसी विचार की अभिव्यक्ति या प्रलेखन है। क्या इस तरह से कागज पर व्यक्त किए गए विचार को रजिस्ट्रीकरण दिया जा सकता है, यह न्यायलय के समक्ष मुद्दा है। यद्यपि आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण हानिरहित प्रतीत होता है और इसके बावजूद कि प्रत्यर्थी सं. 1 पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई है, इस न्यायालय ने आक्षेपित कॉपीराइट

रजिस्ट्रीकरण से संबंधित से संबंधित कुछ पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालना महत्वपूर्ण समझा।

16. ***सबसे पहले,*** न्यायालय प्रासंगिक न्यायिक उदाहरणों की जांच करेगा; ***दूसरा,*** न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण से पहले कॉपीराइट के रजिस्ट्रार को एक अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है; ***तीसरा,*** क्या रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में मनोनियोग का उपयोग शामिल है ताकि व्यक्तियों द्वारा तुच्छ रजिस्ट्रीकरण सुरक्षित न हो; ***चौथा,*** न्यायालय इस तरह के रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव की जांच करेगा जो सामान्य रूप से सार्वजनिक रूप से उसी विचार के अन्य कार्यान्वयनकर्ताओं पर पड़ता है।

17. यह व्यापक संदर्भ में है कि विवादित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण, निर्विवाद रूप से, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा एक सामान्य विचार का प्रलेखन है। पहली नज़र में यह बेतुका लगता है कि एक सामान्य विचार जैसे कि आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण में निहित विचार को केवल इसलिए पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इसे कागज पर लिखने तक सीमित कर दिया गया था, और इसमें कोई प्रयास शामिल नहीं है, कोई पसीना नहीं है, कोई श्रम नहीं है, कोई रचनात्मकता नहीं है - विभिन्न जाँच जो कॉपीराइट योग्यता की जाँच करने के लिए किए गए हैं।

<u>प्रासंगिक न्यायिक उदाहरण</u>

18. इस संदर्भ में, ***आर.जी. आनंद बनाम मैसर्स डीलक्स फिल्म्स और अन्य,*** (1978) 4 एस.सी.सी. 118 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अत्यंत प्रासंगिक है। न्यायलय के समक्ष मुद्दा याचिकाकर्ता का यह दावा था कि उसने वर्ष 1953 में एक नाटक *"हम हिंदुस्तानी"* लिखा था, जिसे बाद में नई दिल्ली के वेवेल थिएटर में अभिनीत किया गया था। यह नाटक लोकप्रिय साबित हुआ और इसे प्रशंसा मिली। इसके बाद, इस नाटक को *"नई दिल्ली"* नामक एक चलचित्र में रूपांतरित किया गया जो सितंबर 1956 में प्रदर्शित किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह पूरी तरह से उसी नाटक पर आधारित है और उसने क्षतिपूर्ति तथा अन्य राहत के लिए वाद दायर किया। यह मामला कॉपीराइट के उल्लंघन के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्रों के उपलब्ध कानून का अध्ययन किया और अनुच्छेद 45 और 46 में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा, जो निम्नानुसार हैं:

> *"**45.** <u>इस प्रकार, स्थिति यह प्रतीत होती है कि एक विचार, सिद्धांत, विषय, या विषय-वस्तु या ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्य सामान्य संपत्ति होने के कारण किसी विशेष व्यक्ति के कॉपीराइट का विषय नहीं हो सकते हैं।</u> किसी भी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी विचार को विषय-वस्तु के रूप में चुनें और उसे अपने तरीके से विकसित करें और विचार को दूसरों से अलग तरीके से व्यवहार करके अभिव्यक्ति करें। जहाँ दो लेखक एक ही विषय पर लिखते हैं, वहाँ समानताएँ होना तय है क्योंकि दोनों का केंद्रीय विचार समान है, लेकिन समानताएँ या*

संयोग अपने आप में साहित्यिक चोरी या चोरी का कोई अपरिहार्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उदाहरण के लिए महान कवि और नाटककार शेक्सपियर को लें जिनके अधिकांश नाटक यूनानी-रोमन और ब्रिटिश पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीज़र आदि जैसी पौराणिक कथाएँ। लेकिन शेक्सपियर द्वारा अपने प्रत्येक नाटक में विषय को प्रस्तुत करने का तरीका इतना ताजा, इतना अलग, इतना काव्यात्मक उत्साह, सुंदरता और पांडित्य से भरा हुआ है तथा इतना नवीन है कि जिसके परिणामस्वरुप अंतिम उत्पाद अपने आप में एक मौलिक कृति बन जाता है। वास्तव में, उनकी अभिव्यक्ति की शक्ति और उत्साह, उनकी शैली की विशिष्टता, वाक्पटुता और उत्कृष्टता तथा नाटकों की करुणा और भावुकता शेक्सपियर के लिए विशिष्ट बन गई है और उनके द्वारा अपनाई गई मूल विषय-वस्तु का बहुत कम हिस्सा ही बचता है। इस प्रकार महान नाटककार के खिलाफ साहित्यिक चोरी का आरोप लगाना बेतुका होगा। वास्तव में, अपनी मूल सोच, योग्यता और निरंतर श्रम के दौरान शेक्सपियर ने एक पुराने विचार को एक नए विचार में बदल दिया है, ताकि उनके प्रत्येक नाटक अंग्रेजी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति बन सकें। यह सही कहा गया है कि "शेक्सपियर का प्रत्येक नाटक एक विस्तारित रूपक है"। इस प्रकार, मूल तथ्य जिसे निर्धारित किया जाना है, जहां प्रतिवादी के खिलाफ वादी द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, यह निर्धारित करना है कि प्रतिवादी ने न केवल कॉपीराइट किए गए कार्य के विचार को अपनाया है या नहीं, बल्कि मामूली परिवर्तनों या अतिशयोक्ति या अलंकरण के साथ तरीके, व्यवस्था, स्थिति-दर-स्थिति, दृश्य-दर-दृश्य को भी अपनाया है या नहीं। वास्तव में, यदि कॉपीराइट किए गए काम के अवलोकन पर प्रत्यर्थी की कृति एक पारदर्शी पुनर्व्याख्यान या

मूल के एक सारवान और महत्वपूर्ण हिस्से की प्रति प्रतीत होता है, तो साहित्यिक चोरी का आरोप साबित होना ही चाहिए। हालांकि यह देखने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि क्या प्रतिवादी ने केवल साहित्यिक चोरी को छुपाया है या वास्तव में उसने मूल को अलग रूप, अलग लहजे, अलग भाव में पुनरुत्पादित किया है ताकि उसके द्वारा अनुकूलित कॉपीराइट कृति विचार में एक नया जीवन डाल सके। बाद के मामले में कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

46. *इस प्रकार, ऊपर विवेचना किए गए विषय-वस्तु पर विभिन्न प्राधिकारियों और निर्णयज विधि पर सावधानीपूर्वक विचार करने और स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित प्रतिपादना सामने आते हैं:*

1. <u>किसी विचार, विषय-वस्तु, विषयों, कथानकों या ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यों का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में कॉपीराइट का उल्लंघन कॉपीराइट किए गए कृति के लेखक द्वारा विचार के रूप, तरीके और व्यवस्था और अभिव्यक्ति तक ही सीमित है।</u>

2. <u>जहाँ एक ही विचार को अलग-अलग तरीके से विकसित किया जा रहा है, यह स्पष्ट है कि स्रोत सामान्य होने के कारण, समानताएँ अवश्य होती हैं। ऐसे मामले में न्यायालयों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कॉपीराइट किए गए कृति में अपनाई गई अभिव्यक्ति की विधा के मौलिक या महत्वपूर्ण पहलुओं पर समानताएं हैं या नहीं।</u> यदि प्रतिवादी का लेखन जहाँ-तहाँ कुछ भिन्नताओं के साथ कॉपीराइट किए गए ग्रंथ की शाब्दिक नकल के अलावा और कुछ नहीं है, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही योग्य होने के लिए अनुकृति (विषय-वस्तु) सारवान और महत्वपूर्ण होनी चाहिए,

जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि प्रतिवादी चोरी के कृत्य का दोषी है।

3. यह निर्धारित करने के लिए कि कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है या नहीं, सबसे निश्चित और सुरक्षित जाँचों में से एक यह देखना है कि क्या पाठक, दर्शक या देखनेवाला दोनों कृतियों को पढ़ने या देखने के बाद स्पष्ट रूप से इस राय से सहमत है और उसे यह स्पष्ट धारणा है कि बाद की रचना मूल की नकल है।

4. जहाँ विषय-वस्तु एक ही है लेकिन अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत और पेश किया गया है जिससे बाद वाली कृति पूरी तरह से नयी कृति बन जाती है, वहाँ कॉपीराइट के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

5. जहां दोनों कृतियों में दिखाई देने वाली समानताओं के अलावा महत्वपूर्ण और व्यापक असमानताएं भी हैं जो मूल की नकल करने के इरादे को नकारती बनाती हैं और दोनों कृतियों में दिखाई देने वाले संयोग स्पष्ट रूप से आकस्मिक हैं, कॉपीराइट का कोई उल्लंघन मौजूद नहीं है।

6. चूंकि कॉपीराइट का उल्लंघन चोरी के कार्य के बराबर है, इसलिए ऊपर विवेचना किए किए निर्णयज विधि द्वारा निर्धारित विभिन्न जांचो को लागू करने के बाद इसे स्पष्ट और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

7. हालाँकि जहाँ प्रश्न किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक द्वारा रंगमंचीय नाटक के कॉपीराइट के उल्लंघन का है, वहाँ वादी का कार्य चोरी को साबित करना अधिक कठिन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि रंगमंचीय नाटक के विपरीत फिल्म का परिप्रेक्ष्य, क्षेत्र और पृष्ठभूमि अधिक व्यापक होती है, जहां प्रतिवादी विभिन्न प्रकार की घटनाओं को प्रस्तुत करके, कॉपीराइट किए गए कार्य में विचार व्यक्त करने के तरीके से भिन्न रंग और

> *स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। फिर भी, यदि फिल्म देखने के बाद दर्शक की यह पूर्णरूपेण धारणा हो जाती है कि फिल्म मोटे तौर पर मूल नाटक की नकल है, तो इसे कॉपीराइट का उल्लंघन साबित कहा जा सकता है।*
>
> (जोर दिया गया)

19. हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्याख्या और अभिव्यक्ति स्व-व्याख्यात्मक है, यह दोहराया जाना चाहिए कि निष्कर्ष यह था कि किसी विचार, विषय-वस्तु, कथ्य, कथानक या ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य में कोई कॉपीराइट नहीं होती है, और यह कि कॉपीराइट विचार के रूप, तरीके, व्यवस्था और अभिव्यक्ति तक ही सीमित है। यदि एक ही विचार को अलग-अलग तरीके से विकसित किया गया है, हालांकि अभिव्यक्ति के तरीके में कुछ मौलिक या सारवान समानताएं हैं, तो कॉपीराइट के उल्लंघन का मुद्दा उत्पन्न होता है। हालाँकि, यदि उसी विचार को अलग-अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है, जिससे बाद का काम पूरी तरह से नए काम में बदल जाता है, तो कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

20. ***अनिल गुप्ता बनाम कुणाल दासगुप्ता,*** 2002 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 250 मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित न्यायपीठ ने याचिकाकर्ता के इस दावे पर विचार किया कि उसने एक रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम *"स्वयंवर"* के विचार की कल्पना की थी, जिसमें वास्तविक जीवनसाथी चयन की प्रक्रिया शामिल थी, जिसे प्रत्यर्थीगण को गोपनीय रूप से बताया गया

था। इसमें प्रत्यर्थीगण ने जोड़ी बनाने के लिए एक बड़े बजट का रियलिटी शो *'शुभ विवाह'* शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर याचिकाकर्ता ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

21. उक्त निर्णय में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा परिकल्पित विचार वैचारिक रूप से नया था और इसे संरक्षित किया जा सकता है, और यह भी कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दी गई अवधारणा की जानकारी गोपनीय थी, और क्या प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता द्वारा विकसित अवधारणा के आधार पर अपना कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि किसी विचार का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। हालाँकि, न्यायालय ने नीचे दिए गए पैराग्राफ में इस मुद्दे को और अधिक विस्तार से समझाने का प्रयास किया:

> "**29.** *किसी विचार का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। लेकिन अगर विचार को पर्याप्त विवरण के साथ एक अवधारणा के रूप में विकसित किया जाता है, तो वह कॉपीराइट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण करने योग्य है। वादी की अवधारणा की नवीनता और नवाचार विवाह के उद्देश्य से जोड़ी बनाने जैसे विषय के साथ रियलिटी टीवी शो के जोड़ने में निहित है। भारतीय पौराणिक कथाओं में उद्धृत स्वयंवर कोई नियमित प्रथा नहीं थी। पौराणिक कथाओं में, मोटे तौर पर हम केवल दो स्वयंवरों के बारे में जानते हैं, एक महाभारत में, जहां चुनाव दुल्हन पर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि किसी भी राजकुमार द्वारा किए जाने वाले वीरता के कार्य पर छोड़ दिया गया था और जो भी ऐसे प्रदर्शन में सफल हुआ, उसे द्रौपदी का हाथ मिला। इसी तरह,*

रामायण में चयन दुल्हन पर नहीं छोड़ा गया था, बल्कि पुनः किसी राजकुमार द्वारा वीरतापूर्ण कार्य के प्रदर्शन पर छोड़ दिया गया था जो शक्तिशाली धनुष (धनुष) को तोड़ सकता था। इसलिए, मौलिकता इस बात में निहित है कि पौराणिक स्वयंवर के माध्यम से विवाह-संबंधी कार्यक्रम और जीवनसाथी के चयन के कार्यक्रम में स्त्री को विभिन्न वर में से एक वर चुनने का विशेषाधिकार दिया जाए तथा इसे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने योग्य बनाया जाए तथा इसे व्यावसायिक विपणन के लिए जांचा जाए। इसलिए, वादी द्वारा दुल्हन को विकल्प देने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जोड़ी बनाने की अवधारणा मूल विचार में एक नई अवधारणा थी जिसे संरक्षित किया जा सकता था।"

(जोर दिया गया)

22. ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

*"**43.** <u>उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब विचार विकसित किया जाता है और भले ही समानताएं हों, कॉपीराइट कार्य में अपनाई गई अभिव्यक्ति के तरीके का पर्याप्त मौलिक पहलू और प्रत्यर्थी का काम कुछ भिन्नताओं के साथ कॉपीराइट कार्य का शाब्दिक अनुकरण है, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।</u> हालांकि मेरे सामने प्रतिवादीगण का तर्क यह है कि वे यह खुलासा नहीं करना चाहते हैं कि शुभ विवाह की अवधारणा और प्रारूप और संरचना क्या है, टीवी रियलिटी शो जिसे वे टेलीविजन पर प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं और जिसके कई एपिसोड शूट कर लिए गए हैं।"*

(जोर दिया गया)

23. न्यायालय *प्रथम दृष्टया* इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रत्यर्थीगण इस अवधारणा से अवगत थे और उन्हें याचिकाकर्ता के काम का उल्लंघन करने से रोकने के लिए व्यादेश दी जानी चाहिए।

24. ***मैटेल आई.एन.सी. और अन्य बनाम श्री जयंत अग्रवाल और अन्य*** (2008) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 1059, में दिए गए निर्णय भी इस विषय पर निर्देशात्मक है। उक्त निर्णय इस न्यायालय की एक समन्वित न्यायपीठ द्वारा याचिकाकर्ता के *"स्क्रैबल"* के नाम से लोकप्रिय होने के संदर्भ में दिया गया था, और शिकायत उन प्रतिवादीगण के खिलाफ थी जिन्होंने *"स्क्रैबुलस"* चिह्न के तहत बोर्ड गेम का एक ऑनलाइन संस्करण शुरू किया था। ***आर.जी. आनंद,*** *(पूर्वोक्त)* को उद्धृत करते हुए, न्यायालय ने कहा कि कॉपीराइट कानून का आवश्यक तत्व यह है कि यह किसी साहित्यिक कृति के लेखक को विचारों और तथ्यों पर संरक्षण प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में इस अवधारणा को आगे स्पष्ट किया, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"**22.** <u>कॉपीराइट कानून के क्षेत्र में विलय के सिद्धांत में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच अंतर करना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह विचार हो, और विलोमतः अभिव्यक्ति एक विचार हो, जिसके परिणामस्वरूप दोनों का अविभाज्य "विलय" हो। इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालयों ने एक विचार की अभिव्यक्ति (कॉपीराइट के माध्यम से) की रक्षा करने से इनकार कर दिया है, जिसे केवल बहुत सीमित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने</u>*

<u>से उस विचार पर ही एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा।</u> हर्बर्ट रोसेन्थल ज्वैलरी कॉर्पोरेशन बनाम कल्पकियन, 446 एफ. 2डी 738 (1971) में निर्णय इस संबंध में दृष्टांत है। वहाँ वादीगण ने प्रतिवादीगण पर वाद दायर कर उन्हें मधुमक्खी के आकार के रत्न पिन बनाने से परहेज करने को कहा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रत्न के आकार की मधुमक्खी की पिन एक विचार था कि इसका कोई भी नकल करने के लिए स्वतंत्र था, जिसकी अभिव्यक्ति केवल कुछ तरीकों से ही संभव हो सकती है; इसलिए, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है। निकोल्स मामले में, न्यायाधीश लर्नड हैंड ने प्रसिद्ध "अमूर्तता" जांच के बारे में बात की, जिसका न्यायालयों को विचार/अभिव्यक्ति द्विभाजन का सामना करने पर पालन करना चाहिएः

"किसी भी कृति पर, और विशेष रूप से एक नाटक पर, बढ़ती व्यापकता के पैटर्न की एक बड़ी संख्या समान रूप से अच्छी तरह से फिट होगी, क्योंकि अधिक से अधिक घटना को छोड़ दिया जाता है। अंतिम कथन शायद नाटक के बारे में सबसे सामान्य कथन से अधिक कुछ नहीं हो सकता है, और कभी-कभी इसमें केवल इसका शीर्षक शामिल हो सकता है; लेकिन अमूर्तता की इस श्रृंखला में एक बिंदु है जहां वे अब संरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अन्यथा नाटककार अपने "विचारों" के उपयोग को रोक सकता था, जिसके लिए उनकी अभिव्यक्ति के अलावा, उनकी रंगमंचीय सामग्री कभी भी विस्तारित नहीं की जाती है।""

(जोर दिया गया)

25. इस आधार पर, न्यायालय ने *प्रथमदृष्टया* निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का कॉपीराइट का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रचनात्मकता का तत्व *"मौलिकता"* की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है।

26. ***संजय कुमार गुप्ता और अन्य बनाम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया पी. लिमिटेड और अन्य,*** (2018) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 10476, में याचीगण ने *"जीतो अनलिमिटेड"* में अपने कॉपीराइट और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जो टेलीविजन पर एक लाइव शो से संबंधित एक अवधारणा थी। इस न्यायालय की एक समन्वित न्यायपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता द्वारा कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अवधारणा मूल नहीं थी और पहले से ही लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध एक अवधारणा पर आधारित थी। याचिकाकर्ता द्वारा ***अनिल गुप्ता*** *(पूर्वोक्त)* पर भरोसा करने को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून ही मान्य होगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी विषय या कथानक के विचार या विषय को साहित्यिक कृति/ नाट्य कृति / संगीतात्मक कृति /कलात्मक कृति में रूपांतरित नहीं किया जाता है, तब तक अपने आप में आवश्यक घटकों के साथ एक अवधारणा कॉपीराइट का विषय नहीं हो सकती है।

27. इस संबंध में, ***संजय सोया प्राइवेट लिमिटेड बनाम नारायणी ट्रेडिंग कंपनी,*** (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन बम. 407, में बॉम्बे हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा लेबल/व्यापार चिह्न में शामिल कलात्मक कृति में कॉपीराइट के दावे के संदर्भ में दिया गया निर्णय भी प्रासंगिक है। न्यायालय ने उल्लिखित किया कि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम के तहत

दिए गए अधिकारों के बीच अंतर है, जिसमें व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत, उल्लंघन के लिए वाद करने के अधिकार सहित एक रजिस्ट्रीकृत मालिक के लिए अलग-अलग अधिकार उपलब्ध हैं, वहीं कॉपीराइट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। वास्तव में, कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण 1886 के बर्न कन्वेंशन **("बर्न कन्वेंशन"**) के अंतर्गत आता, जिसने स्वतः संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया (*यानी संरक्षण किसी भी औपचारिकता के अनुपालन पर सशर्त नहीं होना चाहिए*)। इसलिए, कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्रवाई एक बिना लाइसेंस वाले लेखक द्वारा शुरू की जा सकती है।

28. ***ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे स्टोरीज बनाम पी.ओ.आई. सोशल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य,*** (2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 6390, में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा, *"ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे"* नामक एक कहानी कहने वाले मंच के स्वामित्व और संचालन के वादी के दावे के संदर्भ में था, जहाँ विभिन्न व्यक्तियों की कहानियों को अपलोड और प्रस्तुत किया जाता था। शिकायत वादी की साहित्यिक कृतियों और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ थी। ***ईस्टर्न बुक कंपनी और अन्य बनाम डी.बी. मोदक*** (2008) 1 एस.सी.सी. 1, पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि कॉपीराइट कानून की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक मौलिकता की थी, जो लेखक के साथ-साथ जनता के हित को बनाए रखने में योगदान

देती है और इसका सीधा संबंध है। विचार-अभिव्यक्ति द्विभाजन के क्लासिक मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> *"**25.** वर्तमान मामले में विचार-अभिव्यक्ति द्विभाजन से संबंधित क्लासिक मुद्दे को उठाया गया है। ऊपर उल्लिखित कानून के अनुसार सुस्थापित विधिक स्थिति यह है कि किसी विचार पर किसी भी कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, किसी भी विचार की अभिव्यक्ति का अनुकरण या अनुलिपि नहीं बनाई जा सकती है, और यदि अभिव्यक्ति की अनुलिपि बनाई जाती है, तो यह कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा।*
>
> ***26.** वर्तमान वाद के संदर्भ में, मूल विचार कहानी कहने के मंच का है। इस तरह के मंच के संचालन पर कोई एकाधिकार नहीं हो सकता है। हालाँकि, ऐसे सभी मंच जो विभिन्न व्यक्तियों/विषयों के बारे में कहानियाँ साझा करते हैं, वे उक्त कहानियों को संप्रेषित करने और प्रसारित करने के लिए अपने स्वयं के रचनात्मक तरीकों को सम्मिलित/शामिल करेंगे, जो अभिव्यक्ति का गठन करते हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित है।"*
>
> (जोर दिया गया)

29. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मंच एक-दूसरे की साहित्यिक सामग्री को दोहरा नहीं सकते हैं लेकिन ऐसे मंचों पर कोई प्रतिबंध नहीं दिया जा सकता है। जबकि पक्षकारगण को एक-दूसरे की अधिकृत की गई तस्वीरों, मूल रचनाओं, कहानियों की प्रस्तुति के तरीके आदि का उपयोग करने से रोक दिया गया था, मंच का संचालन प्रतिबंधित नहीं था।

30. ***हुल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम फैंटेसी स्पोर्ट्स माईफैब11 प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** (2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 6591, में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित भी है। इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया यह निर्णय, वादी के कुछ अनूठी विशेषताओं का उपयोग करते हुए एक काल्पनिक खेल मोबाइल एप्लिकेशन के डेवलपर और ऑपरेटर होने के संदर्भ में उत्पन्न हुआ। शिकायत उन प्रतिवादी के खिलाफ थी, जिन्होंने एक नया मोबाइल ऐप पेश किया था और उन्होंने न केवल वादी की अवधारणा का बल्कि उनके कार्यप्रणाली, विशेषताओं और खरीद/बिक्री इंटरफेस के निष्पादन की भी नकल की थी। ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* में निर्णय पर भरोसा करते हुए, न्यायालय वादी के पक्ष में *प्रथमदृष्टया* निष्कर्ष पर नहीं आ सकी और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिद्वंद्वी मोबाइल एप्लिकेशन के बीच समानताएं थीं, लेकिन असमानताएं उससे भी अधिक थीं।

31. ***ईस्टर्न बुक कंपनी*** *(पूर्वोक्त)* का निर्णय भी इस विषय पर ऐतिहासिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या लॉ रिपोर्ट "सुप्रीम कोर्ट केस" जिसके लिए हैड नोट तैयार करने की आवश्यकता थी, कौशल, श्रम और विशेषज्ञता की आवश्यकता थी और इसलिए, एक मूल साहित्यिक कृति का निर्माण किया और क्या प्रत्यर्थीगण ने अपने विधिक खोज सॉफ्टवेयर में उसी की नकल की है। इसका निपटान करने के लिए, माननीय

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों में इस विषय पर कानून को दोहरायाः

> *"**57.** <u>कॉपीराइट अधिनियम मूल विचार से संबंधित नहीं है, बल्कि विचार की अभिव्यक्ति से संबंधित है। कॉपीराइट का मौलिकता या साहित्यिक योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है।</u> कॉपीराइट सामग्री वह है जो लेखक द्वारा अपने कौशल, श्रम और पूंजी के निवेश से बनाई जाती है, हो सकता है कि यह एक व्युत्पन्न कार्य हो जो रचनात्मकता का स्वाद देता हो। जो कॉपीराइट कार्य अस्तित्व में आता है, वह इस अर्थ में मौलिक होना चाहिए कि कार्य में निहित पूर्व-मौजूदा डेटा के चयन, समन्वय या व्यवस्था के आधार पर, लेखक द्वारा चरित्र में कुछ अलग काम किया गया है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के बावजूद, हम सोचते हैं कि कनाडा के न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के कॉपीराइट में लागू होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा निर्णय उन न्यायालयों के निर्णयों तक ही सीमित रहेगा जो लोकाधिकारी क्षेत्र में हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 52 के आधार पर निर्णयों के मूल पाठ में कोई कॉपीराइट नहीं है। <u>किसी संकलन में कॉपीराइट का दावा करने के लिए, लेखक को अपने कौशल और निर्णय के प्रयोग के साथ सामग्री का उत्पादन करना चाहिए जो इस अर्थ में रचनात्मकता नहीं हो सकती है कि यह नई या अस्पष्ट है, लेकिन साथ ही यह केवल श्रम और पूंजी का उत्पाद भी नहीं है। लेखक द्वारा प्रस्तुत व्युत्पन्न कार्य में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के मूल पाठ की कुछ विशिष्ट विशेषताएं और खुशबू होना चाहिए।</u> निर्णय में रखे गए मामूली बदलाव या इनपुट किसी लेखक के कॉपीराइट की जांच को संतुष्ट नहीं करेंगे।*

....

59. *अपीलार्थीगण द्वारा निर्णयों में दी गई उपरोक्त सूचनाओं का कॉपीराइट होता यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते कि जो कोई भी अपने कौशल और श्रम से किसी भी प्रकार का मौलिक किरदार की मूल कृति का निर्माण करता है, उसे उस कृति की प्रतिलिपि बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा और किसी और को उस फसल को काटने की अनुमति नहीं होगी जो कॉपीराइट के स्वामी ने बोई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थीगण ने सामग्री एकत्र की है और काफी मेहनत से निर्णय के मूल पाठ में इनपुट डालकर निर्णय की पठनीयता में सुधार किया है और इसे अपनी शैली में व्यवस्थित किया है, लेकिन इससे रचनात्मकता की न्यूनतम आवश्यकता का आभास नहीं होता है। कृति के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल और निर्णय का प्रयोग तुच्छ है और यह श्रम और निवेश की गई पूंजी के कारण है और इसे विशुद्ध रूप से एक ऐसे कृतिके रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे अपीलार्थीगण द्वारा कुछ मात्रा में श्रम लगाकर लाया गया है।*

60. *हालाँकि कॉपीराइट स्थापित करने के लिए, रचनात्मकता मानक लागू होता है कि कुछ नया या अस्पष्ट होना चाहिए, लेकिन कॉपीराइट का दावा करने के लिए काम में कुछ मात्रा में रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक न्यूनतम स्तर की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। तथ्यों या आंकड़ों या निर्णयज विधि पहले से ही न्यायालय के फैसले की प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए, एस.सी.सी. की रचनात्मकता केवल पहले से प्रकाशित कुछ तथ्यों या सामग्री को जोड़ना, किसी अन्य लॉ रिपोर्ट में प्रकाशित निर्णयज विधि और इसे और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए न्यायालय के निर्णय को अपनी शैली में व्यवस्थित करना और प्रस्तुत करना होगा। चयन*

<u>और व्यवस्था को विशिष्ट और न्यूनतम रचनात्मकता की कमी वाले श्रम, कौशल और पूंजी के निवेश के सर्वोत्तम परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। यह समग्र रूप से पर्याप्त मौलिकता को प्रदर्शित नहीं करता है ताकि लेखक की मूल कृति के बराबर हो। कॉपीराइट का समर्थन करने के लिए, कुछ मूलभूत भिन्नता होनी चाहिए न कि केवल मामूली भिन्नता, न कि उस प्रकार की भिन्नता जहां अभिव्यक्ति के सीमित तरीके/विशिष्ट तरीके उपलब्ध हैं और लेखक उनमें से एक का चयन करता है जिसे सामान्य विविधता कहा जा सकता है। कॉपीराइट के संरक्षण के लिए नवीनता या आविष्कार या अभिनव विचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए न्यूनतम रचनात्मकता आवश्यक है।</u> हमारे विचार में, प्रति-संपादित (कॉपी-एडिटेड) निर्णयों में अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए उपरोक्त इनपुट कॉपीराइट के लिए आवश्यक रचनात्मकता के मानक को नहीं छूते हैं।

(जोर दिया गया)

<u>कॉपीराइट अधिनियम और कॉपीराइट नियम, 2013 के तहत रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया</u>

32. कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान कॉपीराइट अधिनियम के अध्याय X के तहत प्रदान किया गया है। धारा 44 अनिवार्य करती है कि कॉपीराइट कार्यालय में कॉपीराइट का रजिस्टर बनाए रखा जाए, जबकि धारा 45 किसी लेखक या प्रकाशक या किसी कृति के कॉपीराइट में हितबद्ध व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की अनुमति देती है। इस संबंध में नियम कॉपीराइट नियम, 2013 ("**कॉपीराइट नियम**") के अध्याय XIII में निहित हैं।

33. नियम 70, जो प्रासंगिक है, विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है जिसका कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दायर करते समय पालन किया जाना आवश्यक है। सुविधा के लिए, कॉपीराइट नियमावली के नियम 70 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

> *"**70. कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। –** (1) कॉपीराइट के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र-XIV में किया जाएगा और कॉपीराइट के रजिस्टर में दर्ज कॉपीराइट के विवरण में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण आवेदन प्रपत्र-XV में किया जाएगा।*
>
> *(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कृति के संबंध में होगा, और इस संबंध में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन होगा।*
>
> *(3) प्रत्येक आवेदन पर केवल आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो लेखक या अधिकार का स्वामी हो सकता है। यदि आवेदन कॉपीराइट के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे लेखक द्वारा अपने पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ संलग्न किया जाएगा।*
>
> *(4) अप्रकाशित कृति के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ कृति की दो प्रतियां होनी चाहिए।*
>
> *(5) कंप्यूटर प्रोग्राम के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ स्रोत और ऑब्जेक्ट कोड होना चाहिए।*
>
> *(6) किसी कलात्मक कृति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, जिसका उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है [किसी भी वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में], प्रत्येक आवेदन में उस आशय का एक विवरण शामिल होगा और उसके*

साथ व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3 में निर्दिष्ट व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार का एक प्रमाण पत्र होगा, इस आशय का कि ऐसी कलात्मक कृति के समान या भ्रामक रूप से समान कोई व्यापार चिह्न उस अधिनियम के तहत आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, या उस अधिनियम के तहत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(7) डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने में सक्षम किसी कलात्मक कृति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ हलफनामा के रूप में एक बयान होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) यह डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है; और

(ख) इसे औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु पर लागू नहीं किया गया है और पचास से अधिक बार पुनरुत्पादित नहीं किया गया है।

(8) ऐसा प्रत्येक आवेदन कॉपीराइट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा द्वारा दायर किया जा सकता है।

(9) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन की सूचना देगा जो कॉपीराइट के विषय-वस्तु पर दावा करता है या उसका कोई हित है या आवेदक के अधिकारों पर विवाद करता है।

(10) यदि आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर कॉपीराइट रजिस्ट्रार को ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार, यदि आवेदन में दिए गए विवरणों की

शुद्धता के बारे में संतुष्ट है, तो कॉपीराइट रजिस्टर में ऐसे विवरण दर्ज करेगा।

(11) यदि कॉपीराइट रजिस्ट्रार को [उप-नियम (10)] में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आपत्ति प्राप्त होती है, या यदि वह आवेदन में दिए गए विवरणों की शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह उसकी जांच करने के बाद, कॉपीराइट रजिस्टर में कृति के ऐसे विवरण दर्ज कर सकता है जो वह आवश्यक समझता है।

(12) कॉपीराइट रजिस्ट्रार किसी भी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए दायर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का अवसर देगा।

(13) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को केवल तभी पूरा माना जाएगा जब कॉपीराइट रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की एक प्रति कॉपीराइट के रजिस्ट्रार या कॉपीराइट के उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और जारी की जाती है, जिनको प्रत्यायोजित किया गया है।

(14) कॉपीराइट रजिस्ट्रार, यथाशीघ्र, जहां भी संभव हो, कॉपीराइट रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि संबंधित पक्षकारगण को भेजेगा।"

34. प्रासंगिक प्रपत्र XIV, याचिकाकर्ता के अन्य विवरणों के अलावा, केवल *"विवरण का कथन"* और उक्त प्रपत्र के साथ संलग्न *"आगे के विवरण का कथन"* में निहित विवरण की मांग करता है, जो नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

"विवरण का कथन

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या (कॉपीराइट कार्यालय में भरी जानी है)

2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता

3. कृति के कॉपीराइट में आवेदक की हित की प्रकृति

4. कृति का वर्ग और विवरण

5. कृति का शीर्षक

6. कृति की भाषा

7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक की मृत्यु हो गई है, तो उसकी मृत्यु की तारीख

8. क्या कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश और प्रकाशकों का नाम, पता और राष्ट्रीयता

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशक के नाम, पते और राष्ट्रीयताएँ।

11. कृति के कॉपीराइट में शामिल विभिन्न अधिकारों के मालिकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता, जिसमें में प्रत्येक के पास मौजूद अधिकारों की सीमा, साथ ही समनुदेशन और लाइसेंस, यदि कोई हो तो, उसका विवरण।

12. उन व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता, यदि कोई हो, जो कॉपीराइट सहित अधिकारों को सौंपने या लाइसेंस देने के लिए अधिकृत हैं।

13. यदि कृति कोई "कलात्मक कृति" है, तो मूल काम का स्थान, कृति के कब्जे वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता शामिल है। (वास्तुकला संबधी कृति के मामले में, कृति के पूरा होने का वर्ष भी दर्शाया जाना चाहिए)

14. यदि कृति कोई 'कलात्मक कृति' है जिसका उपयोग किया जाता है या [किसी भी वस्तु या सेवा के संबंध में] उपयोग करने में सक्षम है, तो आवेदन में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45 की उप-धारा (1) के परंतुक के निबंधनानुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार से एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।]

15. यदि कृति कोई "कलात्मक कृति" है, तो क्या यह डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्ट्रीकृत है। यदि हां, तो विवरण दें।

16. यदि कृति कोई "कलात्मक कृति" है जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत एक डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने में सक्षम है, तो क्या इसे औद्योगिक प्रक्रिया के रूप में किसी वस्तु पर लागू किया गया है और यदि हां, तो इसका कितनी बार पुनरुत्पादन किया गया है।

17. टिप्पणी, यदि कोई हो।

स्थान ... ...

तिथि ... ...

(हस्ताक्षर)

आगे के विवरण का कथन

(केवल सॉफ्टवेयर, नाट्य, संगीत और कलात्मक कार्यों सहित साहित्यिक कार्यों के लिए)

1. क्या कृति रजिस्ट्रीकृत किया जाना है -

(क) एक मूल कृति है?

(ख) लोकाधिकारी क्षेत्र में किसी कृति का अनुवाद?

(ग) उस कृति का अनुवाद जिसमें कॉपीराइट मौजूद है?

(घ) लोकाधिकारी क्षेत्र में किसी कार्य का रूपांतरण?

(ङ) किसी ऐसे कृति का रूपांतरण जिसका कॉपीराइट मौजूद हो?

2. यदि कृति किसी ऐसे रचना का अनुवाद या रूपांतरण है जिसका कॉपीराइट मौजूद है:

(क) मूल कृति का शीर्षक।

(ख) मूल कृति की भाषा।

(ग) मूल कृति के लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक की मृत्यु हो गई है, तो उसकी मृत्यु की तारीख।

(घ) मूल कृति के प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता, यदि कोई हो।

(ङ) अनुवाद या रूपांतरण के लिए प्राधिकरण का विवरण जिसमें अधिकृत करने वाले पक्ष का नाम, पता और राष्ट्रीयता शामिल है।

3. टिप्पणी, यदि कोई हो। [...]"

35. कॉपीराइट नियमावली के नियम 70(9) के अनुसार, आवेदक को प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन की सूचना देना अनिवार्य है जो कॉपीराइट की विषय-वस्तु का दावा करता है या उसका हित है या उस पर विवाद करता है।

36. कॉपीराइट नियमावली के नियम 70(11) में कहा गया है कि यदि कॉपीराइट रजिस्ट्रार को कोई आपत्ति प्राप्त होती है, या यदि वह "आवेदन में दिए गए विवरणों की शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है", तो वह उसकी जांच

करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, कॉपीराइट रजिस्टर में कृति का विवरण दर्ज कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझती है।

37. कॉपीराइट नियमावली के नियम 70(11) में प्रावधान है कि यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होती है या यदि विवरणों की शुद्धता के बारे में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जा सकती है, जिसके बाद ही कृति का विवरण कॉपीराइट रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, कॉपीराइट रजिस्ट्रार को कुछ विवेकाधिकार दिया गया है *पहला* कि वह पहले आवेदन में दिए गए विवरणों की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करे और *दूसरा,* ऐसी संतुष्टि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जांच करे। इसलिए, ये विवरण वहीं हैं जो ऊपर उल्लिखित प्रपत्र XIV में उद्धृत किए गए हैं और इसमें एक मूलभूत छानबीन शामिल है। कॉपीराइट नियमावली के नियम 70(12) के तहत रजिस्ट्रार पर एक और अधिदेश है कि वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर दे।

38. प्रत्यर्थी सं. 2 (*कॉपीराइट रजिस्ट्रार*) के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विवरणों की शुद्धता की जांच एक प्रशासनिक कार्य है और रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले की प्रकृति पर कोई विचार नहीं किया जाता है तथा कॉपीराइट रजिस्ट्रार केवल स्वतः संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है।

39. अनिवार्य रूप से यह सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रार इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है कि क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला कोई कृति वास्तव में कॉपीराइट योग्य है या नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय की चिंता यह थी कि क्या कॉपीराइट रजिस्टर में केवल एक कागज के टुकड़े पर दर्ज अमूर्त, सामान्य सुविदित विचारों की अभिव्यक्तियों से भरे होने की संभावना होगी (*जैसा कि वर्तमान मामले में प्रतीत होता है*), और यदि प्रदान किए गए विवरण सही हैं, तो क्या रजिस्ट्रार इसे रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य होगा।

40. वेबसाइट पर प्रकाशन का भी कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि केवल रजिस्ट्रीकृत करने के लिए मांगे गए कॉपीराइट का शीर्षक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और उसके दर्शक को यह पता नहीं चल पाता कि वास्तव में क्या रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है। यदि कोई भी फिल्टर, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान में प्रतीत होता है, जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो व्यापार चिह्न से संबंधित जांच रिपोर्ट देता है जो कॉपीराइट किए जाने की मांग की गई कलात्मक कृति के समान या भ्रामक रूप से समान है।

41. इस जांच में न्यायालय की सहायता के लिए, कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्य प्रणाली और प्रक्रिया नियमावली ("**नियमावली**") प्रस्तुत किया गया था। नियमावली *" साहित्यिक कृतियों की <u>जांच और रजिस्ट्रीकरण</u> के*

लिए कॉपीराइट कार्यालय की सामान्य कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को दर्शाती है। संदर्भ की सुगमता के लिए, पैरा 1 को निम्नानुसार उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> *"1. **प्रस्तावना***
>
> *यह दस्तावेज़ साहित्यिक कार्यों की जांच और रजिस्ट्रीकरण के लिए कॉपीराइट कार्यालय की सामान्य कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को दर्शाता है। यह साहित्यिक कार्य आवेदन (नों) की जांच, स्वामित्व के प्रलेखन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है; लेखन की मौलिकता, कॉपीराइट योग्य विषय-वस्तु की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और उन आधारों पर चर्चा करता है जिन पर विसंगति पत्र जारी किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ कॉपीराइट कानून के हर सिद्धांत को शामिल नहीं करता है, दस्तावेज़ में निर्धारित कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में विधि का बल और प्रभाव नहीं है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यालय के कार्य प्रणाली और प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए संबंधित मामले को प्रस्तुत किया गया है; और विभिन्न मुद्दों से संबंधित अस्पष्टता के मामले में, प्रावधानों की समझ को आसान बनाने के लिए निर्णयज विधि का संदर्भ दिया गया है।"*
>
> (जोर दिया गया)

42. नियमावली की धारा 2 अधिनियम में परिभाषित साहित्यिक कार्य की परिभाषाओं को पुनः प्रस्तुत करती है। धारा 3 अनुकूलन के मुद्दे को स्पष्ट करती है, धारा 4 अनुवाद के मुद्दे को स्पष्ट करती है। स्पष्ट रूप से ये धाराएँ विभिन्न जाँच करने वालो के लिए निर्देशात्मक हैं। इस जांच के लिए

नियमावली की धारा 5 महत्वपूर्ण है जिसका शीर्षक "सुरक्षा पूर्वापेक्षाएँ" है और जो "मौलिकता", "कॉपीराइट योग्य लेखन और विषय-वस्तु" और "प्रकाशन" की अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। *"मौलिकता" के भाग के रूप में, नियमावली में कहा गया है कि "कॉपीराइट" कार्यालय यह निर्धारित करने के लिए कृति की जांच करेगा कि क्या यह मौलिकता की आवश्यकता को पूरा करता है और इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि कृति नया, विशिष्ट, अभिनव या विशिष्ट होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार मौलिकता स्थापित करने के लिए प्रत्येक मामले की अलग-अलग गुणागुणों के आधार पर जांच की जाएगी"।*

43. नियमावली की धारा 5(ख) जो *"कॉपीराइट योग्य लेखन और विषय-वस्तु" के लिए प्रावधान करती है,* निम्नानुसार हैः

> ***"ख) कॉपीराइट योग्य*** *लेखन* ***और विषय-वस्तु***
>
> *साहित्यिक वर्ग के तहत किसी कॉपीराइट योग्य विषय-वस्तु के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, इसमें पाठ, नोट्स या प्रतीकों के रूप में न्यूनतम साहित्यिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसे एक पुस्तक, उपन्यास, पत्रिका, सूची, कंप्यूटर प्रोग्राम, तालिका, संकलन, अनुवाद या पहले से मौजूद कृति के अनुकूलन आदि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।*
>
> *कॉपीराइट कार्यालय यह निर्धारित करने के लिए कृति की जांच करता है कि क्या यह कॉपीराइट योग्य विषय-वस्तु है और आवेदन में प्रदान की गई जानकारी और आवेदन के साथ संलग्न*

कृति की भी जांच करता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या कृति साहित्यिक कृति के रूप में योग्य है।"

44. जबकि धारा 6 में *"रजिस्ट्रीकरण पूर्वापेक्षाएँ"* का प्रावधान है जो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण औपचारिकताएं हैं, धारा 9 में विवेचना की गई है कि *"कॉपीराइट योग्य विषय-वस्तु"* के रूप में क्या योग्य हो सकता है, और इसमें पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पुस्तकों के नए संस्करण, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, गीत के बोल, अवधारणा नोट और पत्र शामिल हैं। यह उक्त धारा नीचे दिए गए शब्दों में *"अवधारणा नोट"* को परिभाषित करने का प्रयास करती है:

"अवधारणा नोट

यदि कोई अवधारणा नोट परिभाषात्मक है और केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक अभिव्यक्ति भी है और लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यह कॉपीराइट संरक्षण के लिए पात्र है। अनिल गुप्ता बनाम कुणाल दासगुप्ता मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी विचार का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। लेकिन अगर विचार को पर्याप्त विवरण के साथ एक अवधारणा नोट के रूप में विकसित किया गया है तो वह कॉपीराइट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण करने योग्य है।"

45. नियमावली, <u>हालांकि प्रकृति में अनिवार्य नहीं है,</u> जाँच करने वाले को प्रासंगिक पहलुओं की पहचान करने के लिए <u>सामान्य दिशानिर्देश</u> प्रदान करता है। इसलिए, कुछ मूलभूत छानबीन की परिकल्पना नियमावली में ही की गई है। यह इस प्रख्यान के विपरीत है कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रीकरण बुद्धिरहित और

प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई छानबीन शामिल नहीं है। न्यायालय को उक्त प्रतिपादना को पचाना मुश्किल लगता है, यह देखते हुए कि कोई भी रजिस्टर जिसका रीम में प्रभाव पड़ता है, बिना जाँच किए गए अमूर्त और गैर-रजिस्ट्रीकरण योग्य सामग्री से भरा नहीं जा सकता है।

46. इसके लिए, प्रत्यर्थी सं. 2 के लिए सुश्री निधि रमन, कें.सर.स्था.अधि., ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का आकलन करने में काफी सहायता प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

47. यह कहा गया है कि कॉपीराइट का कानून इस आधार पर विकसित किया गया है कि *"किसी काम में कॉपीराइट उस समय मौजूद होता है जब उसे बनाया जाता है"*, बशर्ते कि यह देश के कानून के वैधानिक ढांचे के भीतर हो।

48. बर्न कन्वेंशन से पहले, प्रत्येक देश में कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएँ थीं और लेखकों को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा की मांग करनी पड़ती थी जो रचनात्मकता में बाधा डालती थी और सुरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कठिन बनाती थी।

49. भारत द्वारा अपनाया गया 1886 का बर्न कन्वेंशन तीन बातों पर आधारित है - बुनियादी सिद्धांत: **राष्ट्रीय व्यवहार** (*हस्ताक्षरकर्ता राज्य विदेशी कृतियों को अपने देश में उत्पन्न होने वाले कृतियों के समान सुरक्षा देने के लिए सहमत होता है*); **स्वतः संरक्षण** (*हस्ताक्षरकर्ता राज्य के विधान में*

निर्धारित संरक्षण के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है); **संरक्षण की स्वतंत्रता** (*जब किसी अन्य देश में उपयोग किया जाता है, तो कृति अपने मूल देश में प्रभावी कॉपीराइट कानून तक ही सीमित नहीं होते हैं*)।

50. यह कहा गया एक सामान्य नियम के रूप में, कॉपीराइट स्वतः एक मूल कृति के निर्माण पर उत्पन्न होता है जिसमें रजिस्ट्रीकरण या जमा जैसी किसी भी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह सिद्धांत बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 5(2) में निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"(2) इन अधिकारों का उपयोग और प्रयोग किसी भी औपचारिकता के अधीन नहीं होगा; ऐसा उपयोग और ऐसा प्रयोग कृति के मूल देश में संरक्षण के अस्तित्व से स्वतंत्र होगा। नतीजतन, इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अलावा, संरक्षण की सीमा, साथ ही लेखक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए निवारण के साधन, विशेष रूप से उस देश के कानूनों द्वारा शासित होंगे जहां संरक्षण का दावा किया जाता है।"*

51. दुनिया भर में कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का अध्ययन करते समय, यह कहा गया कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (**"डब्ल्यू.आई.पी.ओ."**) द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था, और यह पाया गया कि 68 देशों में कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण प्रणाली है जिसमें कॉपीराइट या एक आई.पी. कार्यालय है। जवाब देने वाले 109 देशों में से 95 ने कहा कि उनके पास कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण के लिए एक विधिक प्रणाली है। जबकि भारत जैसे कुछ देशों में

आवेदकों को दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान कृति की एक प्रति जमा करने की आवश्यकता होती है, अन्य देशों को वास्तविक या डिजिटल प्रारूप में किसी प्रकार की प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। कई देशों में जांच प्रक्रिया साधारण औपचारिकता जांच से लेकर अधिक व्यापक प्रक्रिया तक भिन्न-भिन्न थी।

52. कनाडा जैसे देशों में, औपचारिकता आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की समीक्षा की गई थी। मेक्सिको और पराग्वे में, एक औपचारिक जाँच के अलावा, यह स्थापित करने के लिए एक ठोस जाँच की जाती है कि क्या कृति संरक्षित कार्यों की श्रेणियों में आता है और रजिस्ट्रीकरण प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। हालाँकि, कृति की मौलिकता की समीक्षा नहीं की जाती है। कोरिया गणराज्य और थाईलैंड पूर्ण रूप से मौलिक जांच नहीं करते हैं, लेकिन यह जांच करते हैं कि प्रस्तुत कृति कुछ स्तर की रचनात्मकता दर्शाता है या नहीं।

53. सुश्री रमन द्वारा दायर रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों की जाँच को उद्धृत किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कॉपीराइट कार्यालय यह निर्धारित करता है कि क्या विधि की विधिक और औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया था, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कृति का विषय-वस्तु कॉपीराइट योग्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट कार्यालय को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि *"जमा की गई सामग्री का विषय-वस्तु*

कॉपीराइट योग्य है और अन्य विधिक और औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। यदि विषय-वस्तु कॉपीराइट योग्य न हो तो रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार कर दिया जाएगा। जाँच प्रक्रिया के दौरान, अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय इस तरह के प्रश्नों पर विचार करता क) क्या कृति संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉपीराइट संरक्षण के लिए पात्र है; ख) क्या कार्य को अभिव्यक्ति के एक मूर्त माध्यम में व्यक्त किया गया है; ग) कृति मानव लेखक द्वारा बनाई गई थी; घ) क्या कृति का विषय-वस्तु कॉपीराइट योग्य है; ङ) काम पर्याप्त रूप से मौलिक है और; च) कृति स्वतंत्र रूप से बनाया गया था। रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने के खिलाफ अपील की प्रक्रिया के साथ-साथ कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सिविल वाद संस्थित करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है।

54. दूसरी ओर, चीन कॉपीराइट की स्वतः सुरक्षा प्रदान करता है। सिंगापुर, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली नहीं है और कृति के लेखक के पक्ष में कॉपीराइट स्वतः संरक्षण होता है।

55. सुश्री रमन ने जोर देकर कहा कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम और कॉपीराइट नियम रजिस्ट्रार पर यह दायित्व नहीं डालते कि वह बर्न कन्वेंशन द्वारा समर्थित स्वतः संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर किसी कार्य की मौलिकता की प्रकृति और सीमा के बारे में पूर्ण रूप से ठोस जांच करे और किसी कार्य की मौलिकता की जांच करने के लिए कोई मजबूत खोज तंत्र मौजूद

नहीं है। यदि कॉपीराइट नियमावली के नियम 70(10) में विचार किए गए किसी तीसरे पक्षकार द्वारा आपत्ति की गई हो, तो ही ठोस जांच की जाएगी।

<u>विश्लेषण</u>

56. भारत और अन्य देशों में व्यवस्था का इस तरह का विस्तृत मूल्यांकन करने का उद्देश्य हमें मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करना है कि क्या इस मामले में आक्षेपित रजिस्ट्रीकरण से बचने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करना चाहिए। आइए हम इस उद्देश्य के लिए आक्षेपित रजिस्ट्रीकरण की थोड़ी बारीकी से जांच करें। सबसे ***पहले,*** इसे एक अवधारणा माना जा सकता है; ***दूसरा,*** अवधारणा को एक शीर्षक के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है; ***तीसरा,*** घोषणा के अनुसार, प्रत्यर्थी सं.1 इस कृति के मूल लेखक होने का दावा करता है। इस तरह का आवेदन प्राप्त करने के बाद, क्या जाँच करने वाले का यह दायित्व था कि वह आवेदक के कृति को देखे और इस बारे में मूलतः निर्धारण करे कि वह कॉपीराइट योग्य है या नहीं? विधान और उपर उल्लिखित कॉपीराइट अधिनियम के नियम 70(10) और (11) के तहत जांच की एकमात्र गुंजाइश प्रदान की गई है। *"विवरणों की शुद्धता"* की जांच करते समय, प्रपत्र XIV में निर्धारित तत्वों को अनिवार्य रूप से परीक्षक द्वारा पढ़ा जाना चाहिए।

57. इस तरह के मामले में, भले ही आवेदक यह कहता है कि रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला कृति एक मूल कृति है, तब भी यह स्वीकार करना कठिन होगा कि जाँच करने वाला रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जा रही सामग्री के

प्रति पूरी तरह से संशयवादी या असंवेदनशील रहा होगा। भले ही, बर्न कन्वेंशन के अनुसार, स्वतः संरक्षण का सिद्धांत लागू हो सकता है, जैसा कि सुश्री रमण द्वारा दिए गए नोट से स्पष्ट है, दुनिया भर के देश कुछ प्रकार की मूलभूत छानबीन प्रक्रिया प्रदान करते हैं, विशेष रूप से अमेरिका में। इस मूलभूत छानबीन के लिए कॉपीराइट कार्यालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या, कम से कम, *"जमा की गई सामग्री का विषय-वस्तु कॉपीराइट योग्य है।*

58. भारत के लिए, यह आकलन करने के लिए मार्गदर्शन कि क्या कोई विषय-वस्तु कॉपीराइट योग्य है, किसी भी स्थिति में कार्यप्रणाली और प्रक्रिया नियमावली द्वारा प्रदान किया गया है जो आखिरी बार 6 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। नियमावली की धारा 5 में सुरक्षा पूर्व-आवश्यकताएँ प्रदान की गई है और, विशेष रूप से, नियमावली की धारा 9 में इस बात का मार्गदर्शन प्रदान किया कि कॉपीराइट योग्य विषय-वस्तु क्या होगा। हालांकि यह मूल नियमों का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि कॉपीराइट कार्यालय पूरी तरह से संशयवादी नहीं है या रजिस्ट्रीकरण के लिए जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके प्रति असंवेदनशील नहीं है। नियमावली उन बातों प्रतिबिंब और भंडार है जिसे कोई "सर्वोत्तम कार्यप्रणाली" के रूप में वर्णित कर सकता है। यह नियमावली जाँचकर्ता को आवश्यक शिक्षा, जागरूकता और निर्देश प्रदान करता है, ताकि वे अपने सामने प्रस्तुत सामग्री को देख सकें,

विसंगति नोट जारी कर सकें, या विवरण सही न होने के आधार पर कृति को अस्वीकृत कर सकें, या आवश्यकता पड़ने पर जांच कर सकें।

59. हालाँकि, मुद्दा नियमावली को अद्यतन रखने और यह सुनिश्चित करने का है कि यह प्रचलित है, और देश के हाल के कानून को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में, नियमावली की धारा 9 में अवधारणा नोट के पैरा (*ऊपर के पैरा 44 में पुनः प्रस्तुत*), ***अनिल गुप्ता*** *(पूर्वोक्त)* में निर्णय को संदर्भित करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अवधारणा नोट के रूप में विकसित विचार, जिसमें पर्याप्त विवरण होते हैं, रजिस्ट्रीकरण करने योग्य होता है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा इसी आधार पर आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण का बचाव किया गया था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ***अनिल गुप्ता*** *(पूर्वोक्त)* में दिए गए निर्णय में कोई सार्वभौमिक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया था और वास्तव में ***संजय कुमार गुप्ता*** *(पूर्वोक्त)* में एकल न्यायाधीश द्वारा भी इससे असहमति जताई गई थी। देश के किसी एक न्यायालय के एक निर्णय से किसी विशेष पहलू को उद्धृत करना मार्गदर्शन नियमावली के लिए सबसे बेहतरीन कार्यप्रणाली नहीं हो सकती है और इसमें त्रुटियां, अशुद्धियाँ और गलत व्याख्याएँ हो सकती हैं। यदि ऐसा है, तो अधिकांश निर्णायक सिद्धांत वही है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* में उद्धृत किया है और इसलिए, यह तब तक अपरिवर्तनीय है, जब तक कि

माननीय उच्चतम न्यायालय की बड़ी न्यायपीठ द्वारा इसे खारिज नहीं किया जाता।

60. एक तर्क हो सकता है कि कॉपीराइट कार्यालय इस कठिनाई में पड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि, कम से कम, एक शुद्ध विचार, जब कॉपीराइट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा इसकी *बुनियादी छानबीन* करना चाहिए। कॉपीराइट से संबंधित इस न्यायालय के समक्ष अन्य मामलों में, यह उल्लिखित किया गया है कि कॉपीराइट कार्यालय विसंगति नोट जारी करता है, जो सोच-समझकर किए गए को दर्शाता है।

61. रजिस्ट्रार की ओर से कही गई दलीलों में से एक कॉपीराइट अधिनियम की धारा 48 के तहत है, जो निम्नानुसार हैः

> *"48. कॉपीराइट रजिस्टर में दर्ज किए गए विवरण प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा।– कॉपीराइट रजिस्टर में दर्ज किए गए विवरण प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा और उसमें दर्ज किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि होने का दावा करने वाले दस्तावेज या कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित और कॉपीराइट कार्यालय की मुहर से सील किए गए उद्धरण सभी न्यायालयों में बिना किसी अतिरिक्त सबूत या मूल को प्रस्तुत किए बिना साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे।*

62. यह तर्क दिया गया कि रजिस्टर केवल उसमें दर्ज किए गए विवरणों का *"प्रथमदृष्टया"* सबूत है और रजिस्टर की प्रतियां मूल प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सबूत के बिना भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगी। यह स्पष्ट किया जाता है

कि रजिस्टर केवल *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य है और ठोस साक्ष्य नहीं है और इसलिए, रजिस्ट्रार स्वतः घोषणा नहीं करता है कि वह इस कृति का लेखक है। इस न्यायालय की राय में धारा 48 विशुद्ध रूप से साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित प्रावधान है और इस संबंध में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेगी। अन्यथा भी, केवल इसलिए कि रजिस्टर *प्रथम दृष्टया* उसमें दर्ज किए गए विवरणों का प्रमाण है, इसका मतलब यह नहीं है कि रजिस्टर में कोई भी आवेदन दर्ज करने से पहले कोई बुनियादी छान-बीन नहीं की जा सकती। धारा 44, वास्तव में, रजिस्टर को उस रूप में परिभाषित करती है जिसमें लेखकों, प्रकाशकों और *"कॉपीराइट के मालिकों"* के नाम और पते के साथ कृतियों के नाम या शीर्षक दर्ज किए जाने हैं। रजिस्टर में संभवतः ऐसी सामग्री की प्रविष्टियां नहीं हो सकती हैं जो प्रथम सिद्धांतों पर कॉपीराइट योग्य सामग्री भी नहीं है।

63. इसलिए इस न्यायालय की राय में, कॉपीराइट आवेदन की जांच के चरण में एक बुनियादी छान-बीन प्रक्रिया की जानी चाहिए, जिसे कार्यप्रणाली और प्रक्रिया नियमावली में मार्गदर्शन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। नियमावली को बुद्धिमानी से और सटीक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण को व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण का एक दूर देश का चचेरा भाई बना दिया जाय या अन्यथा किसी भी बुनियादी छानबीन से पूरी तरह से अलग रखा जाए। इसलिए कॉपीराइट कार्यालय, भारत

सरकार द्वारा जारी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया नियमावली को बनाए रखा जाए और उसका पालन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर से बेहतरीन कार्यप्रणालियों को भारत में लागू किया जाए, एक ऐसा राष्ट्र जो बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अग्रणी बनना चाहता है।

64. जहाँ तक वर्तमान मामले के विवरणों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण में एक सामान्य विचार की अभिव्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की मांग की है जिसमें स्पष्ट रूप से मौलिकता का अभाव है। चूंकि प्रत्यर्थी सं.1 ने 14 जुलाई, 2022 को कार्यवाही शुरू होने के बाद से और उसके बाद न्यायालय द्वारा निर्धारित एक दर्जन से अधिक तारीखों पर उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है, इसलिए यह तर्क अखंडित रह गया है और इसलिए, इस पर विचार करना होगा।

65. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 13(1)(क) के अनुसार, कॉपीराइट अन्य बातों के साथ-साथ किसी *"मूल"* साहित्यिक कृति में भी मौजूद रहता है। याचिकाकर्ता की इस दलील के अलावा, जिसका खंडन नहीं किया गया है, यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट है कि आक्षेपित रजिस्ट्रीकरण, आभासी प्रदर्शनी की अवधारणा का एक सारांश मात्र है, जो लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसका उपयोग कई लोग कर रहे हैं जो आभासी माध्यम से प्रदर्शनी आयोजित करना चाहते हैं। वास्तव में, आभासी माध्यम आज की तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में अधिकांश लेनदेन का आधार है। यद्यपि, ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* के अनुसार,

किसी विचार का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता है, यह मानते हुए कि यह विचार एक साहित्यिक कृति के रूप में व्यक्त किया गया था, कॉपीराइट योग्य सामग्री के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए, इसे विभिन्न न्यायालय के निर्णयों में व्यक्त किए गए सभी जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा - इसमें, विचार को पर्याप्त विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और रचनात्मकता की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। आक्षेपित रजिस्ट्रीकरण केवल एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें कोई पर्याप्त विवरण नहीं है, बिना किसी निवेश, रचनात्मकता, श्रम और पसीने के, लोकाधिकारी क्षेत्र से लिया गया है, और कागज के एक टुकड़े पर व्यक्त किया गया है।

66. इस संरूपण को, किसी भी तरह से, कॉपीराइट योग्य नहीं माना जा सकता है और इसलिए, कॉपीराइट के रजिस्टर पर बनाए नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि ये जाँच, जैसा कि ***आर.जी. आनंद*** *(पूर्वोक्त)* और अन्य निर्णयों में व्यक्त किया गया है, उल्लंघन कार्यों के संदर्भ में हैं, ये मुद्दे के मूल को संबोधित करते हैं। इसलिए, ***संजय कुमार गुप्ता*** *(उपर्युक्त),* में पैरा 18 में में टिप्पणी किया गया है कि *"जब तक विषय या कथानक आदि के विचार या विषय-वस्तु को साहित्यिक कृति या नाट्य कृति या संगीत कृति या कलात्मक कृति आदि में परिवर्तित नहीं किया जाता है, तब तक अवधारणा अपने आप में अपने आवश्यक घटकों के साथ कॉपीराइट का विषय नहीं हो सकती है, जैसा*

कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विशेष रूप से कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2(म), 14 और 16 के प्रावधानों के संदर्भ में" सही दृष्टिकोण है।

67. जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है, आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण, किसी भी स्थिति में, 'अवधारणा नोट' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और न ही इसे किसी भी अवधारणा का विवरण माना जा सकता है जैसा कि प्रत्यर्थी सं.1 ने 25 अक्टूबर, 2020 के अपने कानूनी नोटिस में दावा किया है। आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण की सामग्री वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने के लाभों और लाभों के सामान्य विवरण से ज्यादा कुछ नहीं है, और वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने की किसी भी *'अवधारणा'* की व्याख्या या वर्णन नहीं करती है। आक्षेपित कॉपीराइट में किसी भी वाक्य को *'अवधारणा नोट'* या *'अवधारणा'* नहीं माना जा सकता है।

68. 'अवधारणा' शब्द को 'एक सिद्धांत या एक विचार' के रूप में परिभाषित किया गया है। आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने के किसी भी सिद्धांत या विचार का खुलासा नहीं करता है और न ही यह वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं या तैयारियों पर कोई चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करता है। इसके बजाय, आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण केवल वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने के विभिन्न लाभों को सूचीबद्ध करता है और इस तरह का विवरण रजिस्ट्रीकृत मालिक को

वर्चुअल एक्सपो आयोजित करने के विचार या अवधारणा पर कोई विशेष अधिकार नहीं दे सकता है।

<u>निष्कर्ष</u>

69. इसलिए, इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक विचार है, जो लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसका कोई विवरण नहीं है, इसका उपचार अमूर्त है, तथा इसकी प्रकृति अत्यंत सामान्य है। इसलिए यह कॉपीराइट योग्य सामग्री नहीं होगी।

70. किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं.1 की अनुपस्थिति के कारण याचिकाकर्ता के प्रकथन अखंडित हैं।

71. तदनुसार, आक्षेपित कॉपीराइट रजिस्ट्रीकरण को हटा दिया जाए और चार सप्ताह की अवधि के भीतर रजिस्टर को तदनुसार ठीक किया जाए।

72. रजिस्ट्री, अनुपालन के लिए कॉपीराइट के रजिस्ट्रार को वर्तमान आदेश की एक प्रति भेजी जाय और सी.जी.एस.सी. कार्यालय को भी समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे सूचित की जाय।

73. न्यायालय सुश्री निधि रमन, कें.सर.स्था.अधि. द्वारा प्रस्तुत व्यापक शोध के लिए उनकी सराहना करता है, जो अमूल्य था।

74. वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उसे निष्फल माना जाता है।

75. निर्णय को इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)
न्यायाधीश

06 मई, 2024/आर.के.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*